

निजामुद्दीन एक्सप्रेस का संचालन अब प्रत्येक मंगलवार एवं गुरुवार को किया जाएगा। दिन अम्बिकापुर से प्रातः 7.30 बजे खाना होगी। वहीं गाड़ी संख्या 22408 हरजत निजामुद्दीन-अम्बिकापुर एक्सप्रेस प्रत्येक रविवार एवं मंगलवार को रात्रि 11 बजे हरजत निजामुद्दीन से खाना होगी। सेवा आवृत्ति बढ़ाए जाने से सरगुजा संभाग के यात्रियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए सहाह में एक अतिरिक्त सीधी रेल सेवा उपलब्ध हो गई है। सांसद चिंतामणि महाराज ने कहा कि अम्बिकापुर से दिल्ली के लिए सहाह में दो दिन दिन संचालन की मांग लंबे समय से की जा रही थी।

संपादकीय

बड़ी दिमागी खोज

रोशनी से न्यूरोसाइंस को समझने में मिली मदद

मानवता के कल्याण के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए, जिस प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी, इस बार चिकित्सा विज्ञान में खोज के लिये दिया जा रहा पुरस्कार उस कसौटी पर खरा उतरता है। मेडिसिन के लिये वर्ष 2026 का नोबेल पुरस्कार अमेरिका और जर्मनी के तीन वैज्ञानिकों को देने की घोषणा की गई है। कार्ल डेसरंथ, पीटर हेगमान और जॉर्ज नेगल को यह सम्मान दिमाग की कोशिकाओं को रोशनी से नियंत्रित करने वाली खोज के लिये मिला है। इस खोज ने दिमाग के अध्ययन करने का एक नया तरीका वैज्ञानिकों को उपलब्ध कराया है। उनकी खोज व अनुसंधान से ‘ऑप्टोजेनेटिक्स’ तकनीक विकसित करने में मदद मिली है, जो मनुष्य की तंत्रिका कोशिकाओं को नियंत्रित करने के लिये रोशनी का प्रयोग करती है। दरअसल, इस तकनीक का विचार इसके जटिल नाम से ज्यादा आसान है। उल्लेखनीय है कि मनुष्य के मस्तिष्क में अरबों नर्व सेल्स यानी न्यूरोन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के जरिये आपस में संवाद स्थापित करते हैं। विज्ञानी लगातार खोज करते रहे हैं कि मस्तिष्क की सक्रियता, याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करने में न्यूरोन्स समूहों की कैसे भूमिका होती है। निस्संदेह, यह वैज्ञानिकों के लिये एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि आधुनिक तकनीकों से दिमाग की गतिविधि पर तो नजर रखी जा सकती थी, लेकिन विभिन्न कोशिकाओं को ठीक से नियंत्रित करना कठिन था। इस खोज की शुरुआत पीटर हेगमान द्वारा हरे शैवाल के रोशनी की ओर तैरने के रहस्य को सुलझाने से हुई। हेगमान और नेगल ने एक ऐसा प्रोटीन खोजा जो नीली रोशनी पड़ने पर आयन चैनल खोलकर इलेक्ट्रिकल हलचल पैदा करता है। वैज्ञानिकों ने इस बात का अध्ययन किया किया कि यह प्रोटीन रोशनी पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। अंततः इस खोज का प्रयोग न्यूरोन्स को रोशनी के प्रति संवेदनशील बनाने के लिये किया गया। इसके बाद ही शोधकर्ता चुनिंदा तंत्रिका कोशिकाओं को सक्रिय या निष्क्रिय करके देख सके कि इसका कैसा प्रभाव होता है।

माना जा रहा है कि दिमाग की कोशिकाओं का नियमन करने वाले स्विच बटन की खोज चिकित्सा विज्ञान में बड़े बदलाव का वाहक बन सकती है। अब तक वैज्ञानिकों को ज्ञात था कि किसी क्रिया या भावना की अभिव्यक्ति में दिमाग का कौन-सा हिस्सा सक्रिय था। लेकिन नई खोज के जरिये वैज्ञानिक पता लगा सकते हैं कि किन खास कोशिकाओं को सक्रिय या शांत करने से यह वास्तविक प्रतिक्रिया सामने आती है। निश्चित रूप से अब विशिष्ट तंत्रिका कोशिकाओं के व्यवहार की व्यापक जानकारी जुटायी जा सकेगी। कह सकते हैं कि दिमाग के व्यवहार को समझने के लिये अब नये रास्ते खुल गये हैं। बहरहाल, यह खोज इस बात का शानदार उदाहरण है कि बुनियादी वैज्ञानिक शोध से कैसे अप्रत्याशित और बड़ी कामयाबी मिल सकती है। शुरुआत में एक छोटे से शैवाल में मौजूद रोशनी के प्रति संवेदनशील प्रोटीन का अध्ययन इस बात के लिये किया गया था कि वह जीव रोशनी पर कैसी प्रतिक्रिया करता है। लेकिन अंततः यह खोज प्रकृति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक, यानी इंसानी दिमाग की प्रामाणिक जांच के लिये एक मजबूत व विश्वसनीय साधन बन गयी। भरोसा है कि यह खोज मानव कल्याण के नये मार्ग खोलेगी। वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि इस खोज के सामने आने के बाद आंखों की रेटिना कोशिकाओं को प्रकाश के प्रति संवेदनशील बनाकर, उन लोगों के जीवन में रोशनी लायी जा सकेगी, जो किसी रोग के कारण दृष्टिहीन हो गए थे। वहीं दुनिया में तेजी से बढ़ रहे दिमागी रोग पार्किंसन के रोग में, खास दिमागी कोशिकाओं को नियंत्रित करके ऐसे रोगी के शरीर में कंपन व अन्य लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकेगा। दूसरी तरफ आधुनिक जीवन शैली से उपजे अवसाद व तनाव के नियंत्रण में भी यह खोज सहायक बन सकती है। उम्मीद है कि यह खोज अवसाद व तनाव के दौरान दिमाग के प्रभावित हिस्सों की पहचान कर सकेगी। इसमें दो राय नहीं कि इस खोज का लाभ आम आदमी तक पहुंचने में अभी कुछ वक लगेगा, लेकिन मनुष्य के जीवन में इस खोज ने एक नई उम्मीद तो जगा दी है।

संपादकीय

बड़ी दिमागी खोज

रोशनी से न्यूरोसाइंस को समझने में मिली मदद

मानवता के कल्याण के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए, जिस प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी, इस बार चिकित्सा विज्ञान में खोज के लिये दिया जा रहा पुरस्कार उस कसौटी पर खरा उतरता है। मेडिसिन के लिये वर्ष 2026 का नोबेल पुरस्कार अमेरिका और जर्मनी के तीन वैज्ञानिकों को देने की घोषणा की गई है। कार्ल डेसरंथ, पीटर हेगमान और जॉर्ज नेगल को यह सम्मान दिमाग की कोशिकाओं को रोशनी से नियंत्रित करने वाली खोज के लिये मिला है। इस खोज ने दिमाग के अध्ययन करने का एक नया तरीका वैज्ञानिकों को उपलब्ध कराया है। उनकी खोज व अनुसंधान से ‘ऑप्टोजेनेटिक्स’ तकनीक विकसित करने में मदद मिली है, जो मनुष्य की तंत्रिका कोशिकाओं को नियंत्रित करने के लिये रोशनी का प्रयोग करती है। दरअसल, इस तकनीक का विचार इसके जटिल नाम से ज्यादा आसान है। उल्लेखनीय है कि मनुष्य के मस्तिष्क में अरबों नर्व सेल्स यानी न्यूरोन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के जरिये आपस में संवाद स्थापित करते हैं। विज्ञानी लगातार खोज करते रहे हैं कि मस्तिष्क की सक्रियता, याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करने में न्यूरोन्स समूहों की कैसे भूमिका होती है। निस्संदेह, यह वैज्ञानिकों के लिये एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि आधुनिक तकनीकों से दिमाग की गतिविधि पर तो नजर रखी जा सकती थी, लेकिन विभिन्न कोशिकाओं को ठीक से नियंत्रित करना कठिन था। इस खोज की शुरुआत पीटर हेगमान द्वारा हरे शैवाल के रोशनी की ओर तैरने के रहस्य को सुलझाने से हुई। हेगमान और नेगल ने एक ऐसा प्रोटीन खोजा जो नीली रोशनी पड़ने पर आयन चैनल खोलकर इलेक्ट्रिकल हलचल पैदा करता है। वैज्ञानिकों ने इस बात का अध्ययन किया किया कि यह प्रोटीन रोशनी पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। अंततः इस खोज का प्रयोग न्यूरोन्स को रोशनी के प्रति संवेदनशील बनाने के लिये किया गया। इसके बाद ही शोधकर्ता चुनिंदा तंत्रिका कोशिकाओं को सक्रिय या निष्क्रिय करके देख सके कि इसका कैसा प्रभाव होता है।

माना जा रहा है कि दिमाग की कोशिकाओं का नियमन करने वाले स्विच बटन की खोज चिकित्सा विज्ञान में बड़े बदलाव का वाहक बन सकती है। अब तक वैज्ञानिकों को ज्ञात था कि किसी क्रिया या भावना की अभिव्यक्ति में दिमाग का कौन-सा हिस्सा सक्रिय था। लेकिन नई खोज के जरिये वैज्ञानिक पता लगा सकते हैं कि किन खास कोशिकाओं को सक्रिय या शांत करने से यह वास्तविक प्रतिक्रिया सामने आती है। निश्चित रूप से अब विशिष्ट तंत्रिका कोशिकाओं के व्यवहार की व्यापक जानकारी जुटायी जा सकेगी। कह सकते हैं कि दिमाग के व्यवहार को समझने के लिये अब नये रास्ते खुल गये हैं। बहरहाल, यह खोज इस बात का शानदार उदाहरण है कि बुनियादी वैज्ञानिक शोध से कैसे अप्रत्याशित और बड़ी कामयाबी मिल सकती है। शुरुआत में एक छोटे से शैवाल में मौजूद रोशनी के प्रति संवेदनशील प्रोटीन का अध्ययन इस बात के लिये किया गया था कि वह जीव रोशनी पर कैसी प्रतिक्रिया करता है। लेकिन अंततः यह खोज प्रकृति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक, यानी इंसानी दिमाग की प्रामाणिक जांच के लिये एक मजबूत व विश्वसनीय साधन बन गयी। भरोसा है कि यह खोज मानव कल्याण के नये मार्ग खोलेगी। वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि इस खोज के सामने आने के बाद आंखों की रेटिना कोशिकाओं को प्रकाश के प्रति संवेदनशील बनाकर, उन लोगों के जीवन में रोशनी लायी जा सकेगी, जो किसी रोग के कारण दृष्टिहीन हो गए थे। वहीं दुनिया में तेजी से बढ़ रहे दिमागी रोग पार्किंसन के रोग में, खास दिमागी कोशिकाओं को नियंत्रित करके ऐसे रोगी के शरीर में कंपन व अन्य लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकेगा। दूसरी तरफ आधुनिक जीवन शैली से उपजे अवसाद व तनाव के नियंत्रण में भी यह खोज सहायक बन सकती है। उम्मीद है कि यह खोज अवसाद व तनाव के दौरान दिमाग के प्रभावित हिस्सों की पहचान कर सकेगी। इसमें दो राय नहीं कि इस खोज का लाभ आम आदमी तक पहुंचने में अभी कुछ वक लगेगा, लेकिन मनुष्य के जीवन में इस खोज ने एक नई उम्मीद तो जगा दी है।

एसवाय कुरेशी

निःसंदेह, चुनाव आयोग व्यक्ति न होकर एक संस्था है। इसकी विश्वसनीयता दशकों में उन आयुक्तों, अधिकारियों, मतदान कर्मियों और मतदाताओं ने बनाई है, जिन्हें भरोसा था कि अपायपर अपने ही नियमों का पालन करते हैं।

कई महीनों से, मतदाता सूची में ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ यानी एसआईआर ने मतदाताओं की परीक्षा में डाल रखा है। सोमवार को, सर्वोच्च न्यायालय में केंद्रीय चुनाव आयोग के फैसले लेने के तौर-तरीके पर सवाल उठे।

न्यायालय उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जो इन खबरों से जुड़ी थीं कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने आयोग के नाम पर लिए गए फैसलों या कामों पर कम से कम 14 बार आपत्तियां जताईं थीं। वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तुरंत पद से हटाने की मांग की। न्यायालय ने इसे अस्वीकार करके सही किया कि केवल अखुबार की खबरों के आधार पर और एकरतर्फा तौर पर ऐसा असाधारण कदम नहीं उठाया जा सकता। लेकिन इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उम्मीद की जाती है कि आयोग के फैसले आम सहमति से हों; जहां आम सहमति संभव न हो, वहां निर्णय बहुमत के आधार पर हो। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने कहा कि अगर रिकॉर्ड से पता चलेगा कि कुछ निर्णय विशेष इस नियम के उलट लिए गए थे तो अदालत उन पर रोक लगा सकती है; उन्हें अधिकार-क्षेत्र से बाहर घोषित कर सकती है। अब एक नोटिस जारी किया गया है—

विसंगति साबित करने में संबंधित लोगों का पक्ष सुना जाए। लेकिन विवाद का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। अब सवाल सिर्फ यह नहीं रहा कि क्या विशेष गहन पुनरीक्षण प्रशासनिक रूप से सुस्पष्ट है। इससे भी पहले एक सवाल उठता है : क्या कुछ विवादित काम कानूनी तौर पर कइकर कि कानूनी फॉर्म में बदलाव के लिए पहले नियमों में संशोधन की जरूरत है। खबरों के मुताबिक, कमिश्नर संधू भी इससे सहमत थे। फिर भी, बदली हुई ऑनलाइन प्रक्रिया ईसीआई नेट पर दिखाई दी। सोमवार को मामला नए मोड़ पर पहुंचा, जब फॉर्म 6 में बदलाव का मुद्दा

2023 के कानून की धारा 18 स्पष्ट है। इसका मुख्य कामकाज आम सहमति से होना चाहिए; जहां पर आयुक्तों की राय अलग-अलग हो, तो फैसला बहुमत के आधार पर लिया जाए। यह सिद्धांत ‘मुख्य



चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों’ से भी पुराना है (संदर्भ : नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल अधिनियम)। मुख्य चुनाव आयुक्त एक अध्यक्ष है, न कि एक कमांडर। सर्वोच्च न्यायालय ने टीएन शेषन मामले में भी यही कहा था। तीन सदस्यों वाली संवैधानिक संस्था में, दो सदस्यों की एक जैसी राय ही बहुमत है। किसी सामूहिक संस्था के भीतर मतभेद होना सामान्य है, यहां तक कि जब सब ‘ठीक’ हो। जो चीज मायने रखती है, वह यह कि बाद में क्या होता है। अगर आयुक्त ‘अ’ कोई एक प्रस्ताव रखता है और बाकी दो ‘भिन्न राय’ दर्ज करते हैं, तो ‘अ’ के प्रस्ताव को ‘केंद्रीय चुनाव आयोग’ का फैसला नहीं कहा जा सकता।

फॉर्म 6 मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत एक कानूनी प्रपत्र है। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ के हवाले से आई रिपोर्ट से पता चला कि आयुक्त जोशी ने मई में एक प्रशासनिक निर्देश के जरिए एसआईआर की जरूरतों में अतिरिक्त प्रावधान जोड़ने पर आपत्ति जताई थी। यह कहकर कि कानूनी फॉर्म में बदलाव के लिए पहले नियमों में संशोधन की जरूरत है। खबरों के मुताबिक, कमिश्नर संधू भी इससे सहमत थे। फिर भी, बदली हुई ऑनलाइन प्रक्रिया ईसीआई नेट पर दिखाई दी। सोमवार को मामला नए मोड़ पर पहुंचा, जब फॉर्म 6 में बदलाव का मुद्दा

उठाया गया। मुख्य न्यायाधीश ने साफ किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसका अनुमोदन नहीं किया था। यह भी कि अदालत इस बात की जांच करेगी कि ‘किसने क्या बदलाव किया है।’ अब यही सवाल केंद्र में हो गया है।

विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद ‘फॉर्म 6’ ने एक और दिलचस्प भूमिका ले ली है। आयोग ने उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों को निर्देश दिया है, जहां एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, कि वे पुरानी और संशोधित वोटर लिस्ट की तुलना करें। फिर उन पात्र मतदाताओं की पहचान की जाए, जिनके नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। उन्हें फिर से शामिल करने में मदद करें। यह सुधारात्मक कदम बहुत अच्छा है। लेकिन जिस मतदाता का नाम 10, 20 या 30 साल से वोटर लिस्ट में था और एसआईआर के दौरान हटाया गया, उसे ‘नए’ मतदाताओं के लिए बने फॉर्म का इस्तेमाल करने और यह झूठा बयान देने के लिए क्यों और कैसे कहा जा सकता है कि वह पहली बार नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर रहा है—नियमों के अनुसार ऐसा आपराधिक कृत्य है, जिसमें एक साल तक जेल की सजा हो सकती है? सूची से हटाया गया मतदाता नया मतदाता नहीं होता। उसे लिस्ट में वापस शामिल किए जाने की जरूरत है, न कि पहली बार पंजीकरण की। अगर मौजूद

फॉर्म इसके लिए सही नहीं हैं, तो नियमों में बदलाव करके एक नया फॉर्म बनाया जाना चाहिए।

पश्चिम बंगाल का मामला बड़ा संस्थागत सवाल खड़ा करता है। जांच-पड़ताल की प्रक्रिया के जरिए 27.16 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने के बाद, खबरों के अनुसार 22.21 लाख लोगों ने नाम वापस जुड़वाने के लिए अपील की गयी है। इसके अलावा, 16.10 लाख अपीलें वे मिलीं, जिनमें उन नामों को चुनौती दी गई, जो मतदाता सूची में शामिल किए गए। खबरों के मुताबिक, कमिश्नर संधू ने फाइल पर पूछा था कि ‘केंद्रीय चुनाव आयोग’ की ओर से यह अपीलें दायर करने के लिए कौन अधिकृत था? सवाल का पूरा जवाब मिलना चाहिए।

गोवा का मामला भी ऐसा ही है, जहां मतदाता सूची पंजीकरण अधिकारियों ने 97 मतदाताओं को लिस्ट में वापस शामिल किए जाने के योग्य पाया, लेकिन केंद्रीय स्तर पर नियंत्रित सॉफ्टवेयर ने अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित होने से पहले उन्हें वापस शामिल करने की इजाजत नहीं दी। सॉफ्टवेयर कानूनी अधिकारियों के फैसलों से ऊपर नहीं हो सकता। ईसीआई नेट एक समानांतर चुनाव अधिकार संस्था नहीं बन सकता।

केंद्रीय चुनाव आयोग ने 26 सितंबर

की प्रेस विज्ञप्ति में कई सुधारों की घोषणा की है : बैठकों से पहले एजेंडा बताया जाएगा, फैसलों की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी, आईटी टीमों द्वारा किए गए बदलावों की संस्थागत स्तर पर जांच होगी, चुनाव आयुक्तों के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। ईसीआई नेट को चुनावी कानूनों के अनुरूप बनाने पर समीक्षा की जाएगी। लेकिन हर सुधार अतीत के बारे में एक सवाल खड़ा करता है। ऐसे सुरक्षा उपाय पहले से स्वचालित क्यों नहीं थे?

केंद्रीय चुनाव आयोग का यह कहना है कि उसके फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे और राय में भिन्ना भी चर्चा का एक अंग होती है। इसीलिए अपनी इस बचाव मुद्रा को अब रिकॉर्ड से साबित करे। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले पर पहले से कोई राय नहीं बनाई है। यानी फाइलों को सच बताने दें। भारत को एक पारदर्शी संस्थागत बही-खाते की जरूरत है : आयोग के सामने क्या प्रस्ताव रखे गए, उसे किसने मंजूरी दी, किसने असहमति जताई, अंत में क्या फैसला हुआ और किसके अधिकार से उसे लागू किया गया।

निःसंदेह, केंद्रीय चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत काफी अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन संवैधानिक आजादी का मतलब कानून से आजादी नहीं है। वह संस्था जो चुनावी कानूनों का पालन करने की मांग करती हो, उसे खुद भी मिसाल पेश करने वाला आचरण दिखाना चाहिए। निःसंदेह, चुनाव आयोग व्यक्ति न होकर एक संस्था है। इसकी विश्वसनीयता दशकों में उन आयुक्तों, अधिकारियों, मतदान कर्मियों और मतदाताओं ने बनाई है, जिन्हें भरोसा था कि अपायपर अपने ही नियमों का पालन करते हैं।

निःसंदेह, एक बात पर किसी फैसले की जरूरत नहीं है: संसद ने तीन सदस्यों वाला आयोग बनाया है और यह तय किया है कि असहमति होने पर फैसला बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। वहीं एक व्यक्ति खुद अपने आप में संस्था की जगह नहीं ले सकता। जब कोई कार्रवाई मतदाता और चुनाव आयोग के नाम पर की जाए, तो लोकतंत्र एक सरल सवाल पूछने का हकदार है : फैसला किसका था?

लेखक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं।

बिहार के विकास के बिना पूरा नहीं होगा विकसित भारत का सपना

कुमार रोहित

भारत जब वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लेकर बढ़ रहा है तो यह प्रश्न अनिवार्य हो जाता है कि 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार की इसमें क्या भूमिका होगी। भारत की जीडीपी में शीर्ष राज्यों का योगदान सराहनीय हो सकता है, लेकिन जब तक देश का पूर्वी हृदयस्थल अपनी पूर्ण क्षमता से आर्थिक उत्पादन, नवाचार और औद्योगिक पुनर्जागरण का केंद्र नहीं बनेगा, विकसित भारत का सपना परिणति तक नहीं पहुंच सकता। बिहार का आर्थिक यथार्थ निराशा के पुराने विमर्श से बाहर निकल चुका है।

2024-25 में राज्य की जीएसडीपी वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर 8.6ब और वर्तमान मूल्यों पर 13.1% दर्ज की गई, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (2023) के अनुसार राज्य की बहुआयामी गरीबी 51.89% (2015-16) से घटकर 33.76% पर आ गई है, जो गरीबी उन्मूलन की सबसे तेज गति है।

बिहार का पिछड़ापन कोई अपरिहार्य स्थिति नहीं, बल्कि विशिष्ट ऐतिहासिक, नीतिगत और संरचनात्मक आघातों का परिणाम रहा है। मगध और वैशाली ने भारत को प्रथम साम्राज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य और चाणक्य का अर्थशास्त्र दिया। नालंदा और विक्रमशिला ज्ञान के वैश्विक केंद्र थे।

किंतु 12वीं-13वीं सदी में इन ज्ञान-केंद्रों पर बर्बर



आघात हुए और औपनिवेशिक काल में 1793 के स्थायी बंदोबस्त’ (जमींदारी व्यवस्था) ने कृषि अर्थव्यवस्था और ग्रामीण समाज को बंधुआ बना दिया। गिरमिटिया प्रथा के तहत लाखों श्रमिकों का पलायन हुआ।

1952 की माल भाड़ा समानीकरण नीति’ ने पूर्वी भारत के खनिजों को पूरे देश में समान लागत पर उपलब्ध कराकर बिहार का औद्योगिक लाभ समाप्त कर दिया। अंततः राज्य विभाजन के बाद समस्त

खनिज संपदा और भारी उद्योग झारखंड चले गए।

आज राज्य की 50% से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है। प्रशासनिक सेवा समेत विविध क्षेत्रों में बिहार की मेधा दमक रही है। इस ब्रेन ड्रेन को रिवर्स ब्रेन गेन’ में बदलने के लिए स्थानीय परिस्थितिकी तंत्र आवश्यक है। गंगा पर राष्ट्रीय जलमार्ग-1 बिहार को सीधे वैश्विक समुद्री व्यापार से जोड़ता है।

राज्य में प्रस्तावित मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क

देश में हुए व्यापक बदलावों को देखने-समझने का अवसर

मनोहर लाल खट्टर

नरेंद्र मोदी जी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष के सफर में भारत ने आर्थिक, तकनीकी, बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन देखा है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक एक-चौथाई सदी का यह पड़ाव राजनीतिक उपलब्धियों से आगे बढ़कर देश में हुए व्यापक बदलाव को देखने-समझने का अवसर प्रदान करता है। आज 7 अक्तूबर 2026 को नरेंद्र मोदी ने एक सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह सार्वजनिक जीवन की ऐसी यात्रा है, जिसकी शुरुआत साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से हुई और 2014 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ी। यह वह दौर है, जिसमें भारत ने आर्थिक, तकनीकी, बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन देखा है। एक-चौथाई सदी का यह पड़ाव राजनीतिक उपलब्धियों से आगे बढ़कर देश में हुए व्यापक बदलाव को देखने-समझने का अवसर प्रदान करता है।

2014 के बाद मोदी सरकार ने बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे, वित्तीय समावेशन, विनिर्माण, सामाजिक कल्याण और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की बढ़ती भागीदारी पर केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है। समर्थक इस अवधि को तेज गति से हुए

राष्ट्र-निर्माण का दौर बताते हैं, जबकि आलोचकों और स्वतंत्र विश्लेषकों ने क्रियान्वयन, संस्थागत प्रक्रियाओं और आर्थिक लाभों के वितरण को लेकर प्रश्न उठाए हैं। इसलिए इस पूरे दौर को समझने के लिए मापनीय बदलावों के साथ-साथ उनसे जुड़े विमर्शों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

इस अवधि की प्रमुख विशेषताओं में से एक ‘डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना’ का विस्तार रहा है। 2015 में शुरू किए गए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में सहायता की, जिसमें पहचान, बैंकिंग, मोबाइल कनेक्टिविटी और सार्वजनिक सेवाएं बड़े पैमाने पर संचालित हो सकें। मार्च 2026 तक भारत में 144 करोड़ से अधिक आधार पहचानें, 57.71 करोड़ जन धन खाते व तेजी से विस्तारित होता डिजिटल सेवाओं का नेटवर्क मौजूद था। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) इस परिवर्तन के सबसे स्पष्ट प्रतीकों में से एक है। वित्त वर्ष 2016-17 में लगभग 2 करोड़ वार्षिक लेन-देन से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई लेन-देन 24,162 करोड़ से अधिक हो गए। यूपीआई का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ। डिजिटल भुगतान ने छोटे व्यवसायों, रेहड़ी-पट्टरी वालों, उपभोक्ताओं और उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में अधिक आसानी से भाग लेने में मदद की। वहीं डिजिटलॉकर, उमंग, कॉमन



सर्विस सेंटर और भारतनेट जैसे प्लेटफॉर्मों ने सरकारी तथा आवश्यक सेवाओं तक नागरिकों की पहुंच का विस्तार किया है।

‘बुनियादी ढांचा’ भी इस अवधि का प्रमुख स्तंभ रहा है। पिछले 12 वर्षों के दौरान भारत ने सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जलमार्गों, आवास, ऊर्जा और शहरी परिवहन में निवेश को तेज किया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2026 तक भारतीय रेल नेटवर्क का 99.6 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका था, जबकि देश का मेट्रो नेटवर्क 1,155 किलोमीटर से अधिक हो गया था। वहीं विनिर्माण और

आर्थिक आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया गया है। ‘मेक इन इंडिया’, उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं और व्यापक ‘आत्मनिर्भर भारत’ ढांचे के जरिए घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने तथा इलेक्ट्रॉनिक्स व दूरसंचार से लेकर फार्मास्यूटिकल्स और रक्षा तक कई रणनीतिक क्षेत्रों में क्षमता विकसित करने का प्रयास किया गया।

इस अवधि में जन धन खाते, आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के लिए आधार तैयार किया, जिससे

सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाई जा सके। आवास, स्वच्छता, खाना पकाने के ईंधन, पेयजल, स्वास्थ्य बीमा और खाद्य सुरक्षा से संबंधित योजनाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर बुनियादी घरेलू जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव में सरकार ने दावा किया कि इस दौरान 25 करोड़ से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए।

कोविड-19 महामारी के दौरान देश ने कठिन डिजिटल प्लेटफॉर्म के सहयोग से दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियानों में से एक संचालित किया जिसके जरिए 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराक दी गईं, जबकि ईसंजीवनी जैसी डिजिटल सेहत पहलों ने टेलीमेडिसिन की पहुंच बढ़ाई।

मोदी काल में भारत ने स्वयं को ग्लोबल साउथ की आवाज, एक प्रमुख प्रौद्योगिकी और विनिर्माण अर्थव्यवस्था तथा जलवायु कार्रवाई से लेकर डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तक विभिन्न वैश्विक पहलों में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में प्रस्तुत किया है। साल 2023 में जी20 की सफल अध्यक्षता ने भारत को विकास संबंधी चिंताओं, डिजिटल समावेशन और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के हितों को अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर अधिक प्रमुखता से रखने का मंच प्रदान किया। डिजिटल भुगतान और आधार से लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण,

सेमीकंडक्टर विनिर्माण और एआई तक, नीतिगत जोर तेजी से स्वदेशी क्षमताओं के निर्माण की ओर बढ़ा है। हालांकि, इस दौर में भारत की यात्रा रोजगार, असमानता, कृषि संकट, केंद्र-राज्य संबंधों, सामाजिक समरसता व विमर्श की गुणवत्ता जैसे अहम प्रश्नों से भी जुड़ी रही है।

प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हरियाणा को भी राष्ट्रीय विकास यात्रा में महत्वपूर्ण निवेश और विकास परियोजनाएं मिली हैं, जिनमें गुरुग्राम मेट्रो, एम्स रेवाड़ी, द्वारका एक्सप्रेसवे तथा रेलवे और राजमार्ग कनेक्टिविटी का विस्तार शामिल है। वहीं स्वास्थ्य, ऊर्जा, विमानन और औद्योगिक बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को भी समर्थन दिया। साल 2026 में हरियाणा जौंद आर सोनीपत के बीच भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन चालित ट्रेन का केंद्र बना। इसके साथ लगभग 14,700 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भी जुड़ी हैं।

नरेंद्र मोदी जी के सार्वजनिक जीवन के इस 25 वर्ष के सफर का महत्व अंततः यात्रा के पैमाने में और उससे उत्पन्न हुई आकांक्षाओं के पैमाने में निहित है। यात्रा का मार्गमाप्यड होगा कि आज की संस्थाओं, बुनियादी ढांचे व तकनीकी क्षमताओं को देश के 140 करोड़ नागरिकों के लिए अवसर, समृद्धि व बेहतर जीवन स्तर में कितने प्रभावी ढंग से बदला जा सकता है। वहीं 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में कैसे देश के हरेक नागरिक के जीवन को जोड़ा जा सकता है।

लेखक केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं।



विकी कौशल की महावतार में तारा सुतारिया पीछे छूटीं श्रद्धा कपूर और हरनाज संधू

अभिनेता विकी कौशल की आगामी पौराणिक फिल्म महावतार की हीरोइन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। खबरों के मुताबिक, इस महा-फिल्म में लीड हीरोइन के रोल के लिए तारा सुतारिया का नाम सबसे आगे चल रहा है। इससे पहले श्रद्धा कपूर और पूर्व मिस यूनिवर्स हरनाज संधू के नाम भी रेस में थे, लेकिन अब तारा सुतारिया ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। हालांकि निर्माताओं की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है।

निर्देशक अमर कौशिक की इस फिल्म से श्रद्धा कपूर और हरनाज संधू का नाम जुड़ने के बाद अब फिल्म गलियारों में चर्चा है कि विकी कौशल के अपोजिट रोल के लिए तारा सुतारिया का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। अगर बात बन गई तो ये पहला मौका होगा, जब विकी और तारा किसी फिल्म में साथ दिखाई देंगे। चर्चा तो ये भी है कि तारा ने इस फिल्म में खासी दिलचस्पी दिखाई है। फिल्म के निर्माता दिनेश विजान हैं।

फिल्म से जुड़े एक करीबी सूत्र ने बताया, महावतार की कास्टिंग को लेकर चर्चाएं पिछले कुछ समय से लगातार बदल रही हैं।

तारा का नाम भी निश्चित रूप से सामने आया है। निर्माता एक ऐसी अभिनेत्री को साइन करना चाहते हैं, जो फिल्म की इस भव्य व काल्पनिक दुनिया में अपनी मजबूत छाप छोड़ सके और तारा इस कसौटी पर खरी उतरती हैं।

तारा पिछली बार सुपरस्टार यश की फिल्म टॉक्सिक में नजर आई थीं।

बता दें कि मैडॉक फिल्म्स के साथ छावा के बाद विकी की ये दूसरी बड़ी फिल्म महावतार होगी, जिसकी शूटिंग जनवरी, 2027 में शुरू होने की उम्मीद है।

इस फिल्म में विकी अमर और न्याय के प्रतीक भगवान परशुराम का मुख्य और शक्तिशाली किरदार निभाते नजर आएंगे।

विशाल पैमाने पर बनने वाली इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्साह है और इसके जरिए विकी एक बार फिर अपने नए अवतार से पर्दे पर धमाल मचाने वाले हैं।

रावी गुप्ता ने बताया कैसे बदल गई टीवी इंडस्ट्री बोलीं- पहले नकारात्मक किरदार को बिल्कुल बुरा दिखाते थे

अभिनेत्री रावी गुप्ता इन दिनों लोकप्रिय सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के दूसरे सीजन में दामिनी (गौतम विरानी की पत्नी) के किरदार में नजर आ रही हैं। अभिनेत्री ने बताया कि पहले की तुलना में आज काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ी है और मुझे लगता है कि आगे भी बढ़ती रहेगी। उन्होंने कहा, इंडस्ट्री में बदलाव आगे भी जारी रहेगा, खासकर तकनीक के मामले में। अगर मैं क्योंकि सास भी बहू की तुलना-2 की तुलना पहले शो से करूं, तो दोनों की तकनीक में जमीन-आसमान का फर्क है।

अभिनेत्री ने अपने किरदार पर बात करते हुए कहा, मेरा किरदार खुद ही एक सरप्राइज है। लोगों को लगा था कि दामिनी निगेटिव होगी, क्योंकि पिछले सीजन में मैंने निगेटिव रोल किया था। सबको लगा कि वह कुछ गलत करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। असल में वह एक आम औरत है, जिसकी अपनी परेशानियां हैं। वह ज्यादा ड्रामा नहीं करती और यही इस किरदार को खास बनाती है।

अभिनेत्री ने बताया कि पहले के मुकाबले अब उन्हें डेली सोप में बदलाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा, पहले के समय में निगेटिव

रोल को बिल्कुल बुरा ही दिखाते थे, जैसे कि उनमें कुछ अच्छा है ही नहीं और उनकी हर चीज को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता था। खासकर महिलाओं के मामले में, अगर किरदार पॉजिटिव है, तो उसे देवी बना दिया जाता था, लेकिन अब मुझे बदलाव नजर आ रहा है। डेली सोप में भी अब किरदारों में गहराई देखने को मिल रही है, जो कि अच्छा बदलाव है।

उन्होंने आगे कहा, एक समय था जब डेली सोप को लेकर सोच बन गई थी कि महिलाओं को हमेशा दबा हुआ दिखाया जाता था। उन्हें तभी अच्छा माना जाता था, जब वह परिवार के लिए कुर्बानी दें। असल, जीवन में इस तरह का दिखावा महिलाओं को पीछे धकेल सकता है। अब मैं देख रही हूँ कि किरदार कैसे बदल रहे हैं। अब डेली सोप में महिलाओं को घरेलू हिंसा और मैरिटल रेप जैसे मुद्दों पर बात हो रही है, जो कि बहुत जरूरी है और ऐसे मुद्दे समाज में बहुत बड़ा असर भी छोड़ रहे हैं।



टैटू स्टूडियो चलाते हैं तो इन बातों का रखें विशेष ध्यान, बनी रहेगी साफ-सफाई

टैटू बनवाने से पहले लोग स्टूडियो की सफाई का खास ध्यान रखते हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से अहम भी है। इसकी पूरी जिम्मेदारी टैटू आर्टिस्ट के कंधों पर होती है, जो स्टूडियो चलाते हैं। अगर आप भी टैटू आर्टिस्ट हैं और अपने स्टूडियो को साफ-सुथरा रखना चाहते हैं तो ये टिप्स आपके लिए अहम हो जाते हैं। इनका ध्यान रख कर स्टूडियो भी साफ रहेगा और आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे।

हाथों की सफाई है जरूरी

हर टैटू स्टूडियो संचालक और कलाकार का सबसे पहला काम होना चाहिए कि वे अपने हाथों को साफ रखें। इसके लिए सबसे पहले तो टैटू बनाने समय खर के दस्ताने पहनें और हर बार जब आप टैटू बनाना शुरू करें तो अपने हाथों को कीटाणुनाशक से साफ करें। साथ ही टैटू बनाने के बाद हाथों को साबुन से धोएं और साफ तौलिये से सुखाएं। यह सुनिश्चित करने से आप और आपका ग्राहक, दोनों सुरक्षित रहेंगे।

उपकरणों को साफ करके रखें

टैटू बनाने समय इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों को साफ रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गंदे उपकरण संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इसलिए टैटू बनाने के बाद उपकरणों को साफ करें और उन्हें कीटाणुनाशक से साफ करने के बाद ही रखें। इसके अलावा टैटू बनाने के बाद अपने उपकरणों को साफ करने के लिए अच्छे क्लीनर का इस्तेमाल

करें। इससे संक्रमण का खतरा कम होता है और ग्राहक का भरोसा भी बढ़ता है।

कपड़ों की सफाई भी है अहम

टैटू स्टूडियो संचालक और कलाकार अपने कपड़ों को भी साफ रखें, क्योंकि गंदे कपड़े भी संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इसलिए अपने कपड़ों को रोजाना धोएं और धुले हुए कपड़ों को ही पहनें। इसके अलावा टैटू बनाने वाले व्यक्ति को भी अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही स्टूडियो में मौजूद सभी लोगों को भी अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए।

इससे सभी सुरक्षित रहेंगे और स्टूडियो का माहौल भी साफ-सुथरा रहेगा।

ग्राहक की त्वचा को साफ करें

टैटू बनवाने वाले व्यक्ति की त्वचा को साफ करना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए आप अपने स्टूडियो में कीटाणुनाशक रखें और टैटू बनवाने वाले व्यक्ति को त्वचा को साफ करने के लिए उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा टैटू बनवाने वाले व्यक्ति की त्वचा पर टैटू बनाने से पहले कीटाणुनाशक लगाने से त्वचा में नमी बनी रहती है और टैटू बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इससे टैटू बनवाने वाले व्यक्ति को भी तसल्ली मिलती है।



गर्भावस्था के दौरान कुछ महिलाओं को मूलने की आदत लगने का अनुभव हो सकता है। यह एक सामान्य समस्या है और इसे लेकर ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इस लेख में हम कुछ प्रमुख कारणों पर चर्चा करेंगे, जिनकी वजह से गर्भवती महिलाओं को मूलने की समस्या हो सकती है। इन कारणों को समझकर आप इस स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकती हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सकती हैं।

हार्मोनल परिवर्तन

गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के शरीर में कुछ हार्मोनल बदलाव होते हैं, जो मानसिक स्थिति पर असर डाल सकते हैं। जैसे-जैसे गर्भ बढ़ता है, शरीर में कुछ हार्मोन का स्तर बदलता रहता है।

इन बदलावों के कारण महिलाओं को, भूलने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

इस स्थिति को समझकर आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सकती हैं और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह ले सकती हैं।

नींद की कमी

गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को अक्सर नींद की कमी का सामना करना पड़ता है।

गर्भावस्था के दौरान कुछ महिलाओं को क्यों होने लगती है भूलने की आदत? जानिए पांच कारण

पेट बढ़ने और असुविधाजनक महसूस होने के कारण अच्छी नींद लेना मुश्किल हो जाता है।

इसके अलावा रात में बार-बार बाथरूम जाना भी एक बड़ी समस्या होती है। नींद की कमी के कारण महिलाओं को दिन में थकान और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, जिससे भूलने की समस्या भी बढ़ सकती है। ऐसे में रोजाना 8 घंटे की नींद सुनिश्चित करें।

तनाव और चिंता

गर्भावस्था एक सुखद अनुभव होने के साथ-साथ कई चुनौतियों से भरी होती है। इस दौरान तनाव और चिंता होना सामान्य है, लेकिन ये भी भूलने की आदत का कारण बन सकती हैं।

आने वाले बच्चे की जिम्मेदारियां, शारीरिक बदलाव और परिवार के अन्य सदस्यों की अपेक्षाएं इन समस्याओं को बढ़ा सकती हैं।

इस स्थिति को बेहतर तरीके से संभालने के लिए योग, ध्यान या अन्य आरामदायक गतिविधियों का अभ्यास करना फायदेमंद हो सकता है।



पोषण की कमी

सही पोषण लेना गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर खाने-पीने में जरूरी विटामिन और खनिजों की कमी हो तो इसका असर दिमाग की कार्यप्रणाली पर पड़ सकता है, जिससे भूलने की समस्या हो सकती है।

इसलिए, गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार लेना बेहद अहम है।

इसके अलावा पानी का पर्याप्त सेवन भी जरूरी है, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो और दिमाग सही तरीके से काम कर सके।

उम्र का प्रभाव

जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे दिमाग की कार्यप्रणाली धीमी होती जाती है। जिससे भूलने की समस्या बढ़ सकती है। गर्भावस्था के दौरान भी यही सच लागू होता है।

युवा महिलाएं कम भूलती हैं, जबकि उम्रदराज महिलाओं को ज्यादा भूलने की समस्या होती है।

इसलिए, उम्र का ध्यान रखते हुए अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना जरूरी है, ताकि भूलने की समस्या कम हो सके।

माधुरी के सामने फैन ने उतारी जैकेट, टीशर्ट पर ये तस्वीर देख शर्माई एक्ट्रेस

जैकेट उतारकर नाचने लगा कंटेस्टेंट

प्रोमों में शरद राजपूत 'फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट' जीतकर हॉट सीट तक पहुंचते हैं। माधुरी के सामने बैठकर वह काफी खुश नजर आते हैं, क्योंकि वह अभिनेत्री के बहुत बड़े फैन हैं। इसके बाद शरद अपनी जैकेट उतारते हैं और डांस करने लगते हैं। तभी उनकी टी-शर्ट पर माधुरी की तस्वीर नजर आती है। यह देखकर माधुरी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। शरद बताते हैं कि उन्होंने माधुरी की लगभग सभी फिल्मों देखी हैं और उन्हें अभिनेत्री की फिल्मों से जुड़ी कई बातें भी याद हैं। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है और बात धीरे-धीरे शरद की निजी जिंदगी तक पहुंच जाती है।

वयों हंस पड़ी ऑडियंस?

माधुरी शरद से उनकी पत्नी के बारे में पूछती हैं। इस पर शरद मुस्कराते हुए कहते हैं, 'वो मेरी सारी बातें सुनती हैं।' शरद की बात सुनकर माधुरी तुरंत

मजाकिया अंदाज में पूछती हैं, 'सिर्फ सुनती हैं या कभी-कभी ऑर्डर भी देती हैं?' माधुरी का यह सवाल सुनकर सेंट पर मौजूद सभी लोग हंस पड़ते हैं। शो के इस प्रोमो से साफ है कि 'कौन होनार करोड़पति' में माधुरी सिर्फ सवाल-जवाब करती ही नहीं, बल्कि कंटेस्टेंट्स के साथ उनकी जिंदगी और पसंद-नापसंद को लेकर हल्की-फुल्की बातचीत भी करती नजर आएंगी। यह शो 12 अक्टूबर से शुरू होगा और सोमवार से शनिवार रात 9 बजे सोनी मराठी और सोनी लिव पर प्रसारित किया जाएगा।



खास-खबर

ग्रामीणों की बहुप्रतीक्षित मांग हुई पूरी, जोरडाझरिया को मिला नया सामुदायिक भवन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण अधोसंरचना और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में फरसाबहार तहसील के ग्राम पंचायत जोरडाझरिया के ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही सामुदायिक भवन की मांग पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक श्री विष्णु देव साय के विधायक मद से स्वीकृत 10 लाख रुपए की लागत से गांव में सामुदायिक भवन का निर्माण पूर्ण किया गया है। नए सामुदायिक भवन के निर्माण से ग्रामीणों को सामाजिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए गांव में ही सुविधाजनक स्थान उपलब्ध हो गया है। अब ग्रामीणों को विभिन्न आयोजनों के लिए दूसरे स्थानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भवन का उपयोग सामाजिक कार्यक्रमों, बैठकों एवं अन्य सामुदायिक गतिविधियों के लिए किया जा सकेगा। गांव में इस सुविधा के उपलब्ध होने से सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

युवाओं को नवाचार और स्टार्टअप के अवसरों की जानकारी

रायपुर। युवाओं को नवाचार, स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसरों से जोड़ने के उद्देश्य से सेवा संकल्प अभियान के तहत सूरजपुर के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज पर कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें शासकीय वेंटरनरी कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। कार्यशाला में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के प्रबंधक तथा मुख्य वक्ता अवधेश कुशवाहा ने पीपीटी के माध्यम से इनोवेशन पर पंजीवन की प्रक्रिया समझाई। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर पंजीकृत प्रतिभागियों को नवाचार से जुड़े अपने विचार प्रस्तुत करने और उन्हें आगे बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं।

छत्तीसगढ़ में लक्ष्य शत-प्रतिशत बोनी पूर्ण

रायपुर। प्रदेश में खेतों में बोनी का कार्य लगभग अंतिम चरण पर है। 6 अक्टूबर की स्थिति में राज्य के 48.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों में लक्ष्य का शत-प्रतिशत बोनी पूर्ण हो चुकी है। इस खरीफ सीजन में 48.69 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश किसानों को सुगमता से मिले खाद-बीज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों को खेती-किसानी में सहूलियतें प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक सहयोग करने संबंधित अधिकारियों निर्देशित किए गए हैं। उन्होंने किसानों को उनकी मांग के अनुसार सुगमता के साथ प्रमाणित खाद-बीज का वितरण करने को कहा हैं। खाद-बीज वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कड़ी कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए हैं।

सरकार आपके द्वार से गांव तक पहुंची शासकीय सेवाएं, सेमरा के सेवा सेतु शिविर में एक ही स्थान पर मिला योजनाओं का लाभ

पीएम आवास की चाबी से आयुष्मान कार्ड तक, विभिन्न योजनाओं से बड़ी संख्या में हितग्राही हुए लाभान्वित

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत 'सेवा सेतु' अभियान-सरकार आपके द्वार के माध्यम से शासकीय योजनाओं और सेवाओं को नागरिकों के और करीब पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत सेमरा स्थित हाई स्कूल परिसर में विशेष सेवा सेतु शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों की योजनाओं और सेवाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के साथ पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही लाभान्वित किया गया।

शिविर में आयोजित आजीविका ऋण मेले के माध्यम से ग्रामीणों एवं स्व-सहायता समूहों को स्वरोजगार और आजीविका गतिविधियों से जोड़ने की दिशा में विशेष पहल की गई। मेले में 908 प्रकरणों में 19.43 करोड़ रुपये की राशि प्रेषित की गई। इसके साथ ही 537 प्रकरणों में 13.41 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई तथा 281 प्रकरणों में 7.90 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया गया। इससे ग्रामीणों और स्व-सहायता समूहों को अपनी आजीविका गतिविधियों को आगे



बढ़ाने के लिए आर्थिक सहयोग मिला। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर नागरिकों को योजनाओं, पात्रता और लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं और आवश्यकताओं को सुना तथा पात्रतानुसार विभिन्न सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने विभागीय स्टॉलों का अवलोकन कर उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की जानकारी ली तथा ग्रामीणों से संवाद भी किया।

शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के हितग्राहियों को

आवास की चाबी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के साथ आयुष्मान कार्ड, वय वंदन योजना कार्ड, ट्राईसाइकिल, रीजलचेयर, नैनो यूरिया और स्कोलर कार्ड सहित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ प्रदान किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अन्नप्राशन और गोद भराई कार्यक्रम आयोजित कर मातृ एवं शिशु पोषण का संदेश दिया गया। हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं एवं पोषण से संबंधित जानकारी भी दी गई। विभिन्न विभागों के अधिकारियों-

ने नागरिकों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। सेवा संकल्प अभियान के तहत 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक विभिन्न सेवा गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 'सेवा सेतु' अभियान-सरकार आपके द्वार के माध्यम से नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की योजनाओं, सेवाओं और आवश्यक मार्गदर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कार्यक्रम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

अंतिम व्यक्ति का उत्थान और विकास ही हमारी प्रतिबद्धता: राजस्व मंत्री

सुशासन और सर्वव्यापी विकास का नया दौर, योजनाओं का मिला लाभ, तो संवर गया जीवन



पिता मदन लाल के निर्माणाधीन घर का अवलोकन किया, वर्ष 2025-26 के तहत स्वीकृत इस पक्के आवास हेतु 1 लाख 20 हजार रुपये की राशि प्रदान की जा रही है, साथ ही परिवार को 90 दिनों का मनरेगा रोजगार भी

उपलब्ध कराया जा रहा है।

हितग्राहियों के सुखद अनुभवों को सुनकर राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के मूलमंत्र पर कार्य कर रही

बहुआयामी विकास का केंद्र बनी सरकारी योजनाएं

लाभार्थी परिवार की श्रीमती हेमेश्वरी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार की विकासपरक नीतियों के प्रति गहरा आभार जताया। उन्होंने बताया कि सरकार की एकीकृत कल्याणकारी सोच से उनके परिवार की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। श्रीमती हेमेश्वरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से हमें न केवल सुरक्षित और पक्का घर मिला है, बल्कि इसके साथ उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन मिलने से धुएँ से मुक्ति मिली है। जल जीवन मिशन (नल-जल योजना) के माध्यम से अब हमारे घर के भीतर ही स्वच्छ पेयजल आसानी से उपलब्ध हो रहा है। इसके अलावा, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'महतारी वंदन योजना' से हर महीने मिलने वाली वित्तीय सहायता महिलाओं के स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का बड़ा आधार बन चुकी है। इस राशि का उपयोग हम घर की आवश्यक दैनिक जरूरतों और बच्चों की देखभाल में सहूलियत के साथ कर पा रहे हैं।

है। हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का प्रकाश पहुंचाना है।

जब एक ग्रामीण परिवार को अपना पक्का मकान मिलता है, बहन-बेटियों को रसोई गैस और घर पर ही शुद्ध जल की सुविधा मिलती है, तथा महतारी वंदन योजना के माध्यम से मातृशक्ति का आर्थिक सशक्तिकरण होता है, तब

सही मायनों में रामराज्य और सुशासन की संकल्पना साकार होती है।

राज्य सरकार हर पात्र नागरिक को उसका हक और सम्मान दिलाने के लिए पूर्ण पारदर्शिता तथा संवेदनशीलता के साथ निरंतर प्रयासरत है। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारी तथा ग्रामीणों की मौजूदगी रही।

सेवा संकल्प में कलेक्टर ने वृद्धजनों का किया सम्मान

100 वृद्धजनों की निःशुल्क बीएमडी जांच, विशेषज्ञों ने बताए हड्डियों और जोड़ों की देखभाल के तरीके

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत रायगढ़ जिले में 1 से 15 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को किरोड़ीमल जिला चिकित्सालय में वृद्धजनों के सम्मान एवं स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने वृद्धजनों का सम्मान करते हुए उनके बेहतर स्वास्थ्य एवं सुखद जीवन की कामना की।

इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ अधिजीत बबन पट्टारे, नगर निगम आयुक्त वृजेश सिंह क्षत्रिय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल कुमार जगत, सिविल सर्जन डॉ. दिनेश कुमार पटेल, डीपीएम सुश्री रंजना पैकरा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में 87 वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा आवश्यक चिकित्सकीय सेवाएं एवं परामर्श उपलब्ध



कराया गया। जर्जरतमंद 15 वृद्धजनों को छड़ी और 6 वृद्धजनों को वॉकर प्रदान किए गए। वहीं 60 वृद्धजनों को श्रीफल एवं शॉल भेंटकर सम्मानित किया गया। वृद्धजनों की हड्डियों की मजबूती की जांच के लिए निःशुल्क बीएमडी (बोन मिनरल

डेंसिटी) जांच की सुविधा भी रखी गई, जिसका लगभग 100 वृद्धजनों ने लाभ लिया। जांच के साथ वृद्धजनों की हड्डियों एवं जोड़ों की देखभाल तथा बढ़ती उम्र में शारीरिक सक्रियता बनाए रखने के संबंध में चिकित्सकीय जानकारी दी गई।

बुनगा के पांच आंगनबाड़ी केंद्रों में हुआ आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। सेवा संकल्प अभियान के तहत रायगढ़ जिले के विकासखंड पुर्बौर के ग्राम बुनगा के पांच आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सरपंच बेदुप्रकाश साव ने केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों के लिए संचालित योजनाओं का लाभ लेने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया।

महिला एवं बाल विकास विभाग की श्रीमती पुष्पमती चौहान तथा आयुर्वेद चिकित्सा



अधिकारी डॉ. अजय नायक ने अपने-अपने विभाग की योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी। आयुर्वेद विभाग द्वारा कार्यक्रम में शामिल महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा आवश्यकता अनुसार औषधियों का वितरण किया गया। साथ ही स्वस्थ जीवनशैली और नियमित स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में आवश्यक समझावश दी गई। कार्यक्रम

प्रयोगशालाओं में परीक्षण कार्य तेजी से जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कृषि विभाग की प्रयोगशालाओं द्वारा उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण कार्यों को नियमित रूप से संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2026-27 के खरीफ मौसम के दौरान कुल 650 नमूनों के परीक्षण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरुद्ध अब तक 340 नमूने प्राप्त हो चुके हैं, इनमें से 265 नमूनों के परीक्षण परिणाम जारी किए जा चुके हैं, जबकि 75 नमूनों पर परीक्षण की प्रक्रिया अभी जारी है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में आवश्यक रसायन, यंत्र और उपकरण उपलब्ध हैं। कुल 13 स्वीकृत पदों में से 07 पद भरे हुए हैं, और तकनीकी कार्यों के लिए एक सहायक संचालक कृषि तथा एक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को भी प्रतिनियुक्त किया गया है।

SAIRAM
Mobile Accessories

मोबाईल शॉप में कार्य करने हेतु लड़कों की आवश्यकता है

7000415602

Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

चौरसिया ज्वेलर्स

आकर्षक सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता

बेन्वेक्स एवं ग्रहलत उपलब्ध यहां उचित व्याज दर पर धरवी रखी जाती है

मुक्तिधाम रोड, रामनगर, सुपेला, भिलाई

9827938211, 9827171332

CAR DECOR

House Of Exclusive
Seat Cover,
Car Stereos Matting &
Sun Control Film &
Other Accessories

Shop No.3 Nafish Tower,
Opp. Indian Coffee House,
Akashganga, Bhilai

Mo.9300771925, 0788-4030919

K. Satyanarayan

ROCKEY INDUSTRIES FURNITURE PALACE

Deals in: (Steel & Wooden)
Luxury & Imported Furniture

Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 22964330

Shri Vijay Enterprises

Sanitarywares, Tiles,
CPVC Pipes &
Bathroom Fittings etc.

Supela Market, Bhilai
PH. 0788-4030909, 2295573

खास खबर

राजनांदगांव में 60 बोरी नकली-पोटाश जब्त



राजनांदगांव। राजनांदगांव में खाद की अवैध बिक्री रोकने कृषि और राजस्व विभाग की टीम ने कार्रवाई की। डोंगरांव में टीम ने 60 बोरी यानी 3 टन आईपीएल पोटाश जब्त किया। बोरियों पर 60 प्रतिशत पोटाश होने का दावा था, लेकिन रायपुर लैब की जांच में सिर्फ 3 प्रतिशत पोटाश मिला। छुरिया विकासखंड के बम्हनी चारभांउ निवासी राजेंद्र मिश्रा पोटाश बेच रहा है। टीम ने उसे रोककर खाद से जुड़े वैध दस्तावेज मांगे, लेकिन वह कोई कागज नहीं दिखा सका। इसके बाद खाद जब्त कर सैंपल जांच के लिए रायपुर लैब भेजा गया। पूछताछ में राजेंद्र ने बताया कि वह खाद कबीरधाम जिले से लेकर आया था। इसके बाद कृषि विभाग की टीम ने उसके बताए स्थान पर छापा मारा। वहां भी खाद के भंडारण या बिक्री का कोई लाइसेंस नहीं मिला। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस और संबंधित विभाग की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है।

कंट्रोल रूम में डॉयल 112 के आरक्षक की मौत

धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में डॉयल 112 के आरक्षक के आत्महत्या का मामला सामने आया है। कंट्रोल रूम में उसकी फांसी के फंदे पर लटकी हुई लाश बरामद हुई है। कुरुद का निवासी ओमप्रकाश सोनवानी की इयूटी बीटी रात डायल 112 के कंट्रोल रूम में तैनात था। घटना की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल आरक्षक के आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि घटना से पहले आरक्षक की किसी से बातचीत हुई थी या नहीं और क्या किसी तरह का तनाव या अन्य वजह सामने आई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के आधार पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

दुर्ग भिलाई के बस्तियों में पहुंची पुलिस की टीमें, जांच में मिले धारदार हथियार, शराब एवं सदिग्ध वाहन

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। दुर्ग पुलिस की विशेष चेकिंग के दौरान पुलिस की टीमें खुसीपार व मोहन नगर क्षेत्र की बस्तियों में पहुंचीं। गुंडा-बदमाशों, वारंटियों एवं सदिग्ध व्यक्तियों के ठिकानों पर तलाशी के दौरान पुलिस ने धारदार हथियार, शराब व सदिग्ध वाहन मिले। पुलिस ने इन सभी को जब्त कर लिया है। विशेष अभियान में दुर्ग अनुभाग के 67, भिलाई नगर अनुभाग के 63 तथा छावनी अनुभाग के 55 सहित कुल 185 पुलिस अधिकारी-कर्मचारी तैनात रहे। दुर्ग पुलिस का विशेष जांच अभियान मंगलवार तड़के 4 बजे से सुबह 8 बजे तक चला। पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक साथ विशेष चेकिंग अभियान प्रारंभ किया गया। अभियान के



दौरान पूर्व से चिन्हित फरार गुंडा-बदमाश, निगरानी बदमाश, वारंटी एवं आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों की तस्दीक की गई तथा उनके संभावित ठिकानों एवं निवास स्थानों की जांच की गई। इसके साथ ही अन्य क्षेत्रों से आकर संबंधित थाना क्षेत्रों में निवास कर रहे सदिग्ध एवं अनाधिकृत व्यक्तियों की जानकारी संकलित कर उनकी पहचान एवं दस्तावेजों का सत्यापन किया गया।

पुलिस टीमों द्वारा सदिग्ध गतिविधियों वाले स्थानों तथा ऐसे व्यक्तियों के घरों की तलाशी ली गई, जहां अवैध राइफ पदार्थ, शराब अथवा हथियार रखे जाने की संभावना थी।

अभियान के दौरान दुर्ग अनुभाग में उरला, अंबेडकर नगर, बांबे आवास, शंकर नगर, जवाहर नगर एवं ग्रीन चौक क्षेत्र में विशेष तलाशी एवं चेकिंग की गई। भिलाई नगर

अनुभाग के तहत फरीद नगर, डेरा बस्ती, सुपेला क्षेत्र सहित अन्य चिन्हित स्थानों पर सदिग्ध व्यक्तियों एवं निवासरत लोगों की तस्दीक की गई। छावनी अनुभाग के तहत खुसीपार थाना क्षेत्र अंतर्गत देवार बस्ती एवं अटल आवास में घर-घर पहुंचकर निवासरत व्यक्तियों की जानकारी एवं दस्तावेजों का सत्यापन करते हुए तलाशी की गई। जांच के दौरान विभिन्न स्थानों से धारदार हथियार, अवैध शराब। एक सदिग्ध बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की गई है।

विशेष अभियान में संबंधित थाना/चौकी के पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में समन्वित रूप से चेकिंग एवं तलाशी कार्रवाई की गई। पुलिस टीमों द्वारा प्रातःकालीन समय में एक साथ विभिन्न स्थानों पर

कोरबा में नाबालिग से रेप व छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार

कोरबा। कोरबा के उरगा थाना पुलिस ने महिला अपराध और अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में शिकायतकर्ता ने उरगा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी 19 सितंबर 2026 को सुबह करीब 9:30 बजे स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली थी। वह स्कूल नहीं पहुंची। परिजनों ने



अज्ञात व्यक्ति पर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की आशंका जताई थी। पुलिस ने धारा 137(2) बीएनएस में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी मुकेश यादव उसे बहला-फुसलाकर ले

पहुंचकर सदिग्ध व्यक्तियों की तस्दीक, निवास एवं दस्तावेजों का सत्यापन तथा अवैध हथियार एवं अन्य सदिग्ध वस्तुओं की जांच की गई। दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि अपने क्षेत्र में निवास करने वाले सदिग्ध व्यक्तियों, अवैध हथियार, मादक पदार्थ, शराब अथवा अन्य आपराधिक गतिविधियों की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।

मकान मालिक एवं नागरिक अपने यहां निवासरत व्यक्तियों की आवश्यक जानकारी एवं पहचान का सत्यापन करें तथा अपराध की निर्यंत्रण में पुलिस का सहयोग करें। दुर्ग पुलिस द्वारा अपराधियों एवं सदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी तथा इस प्रकार की विशेष चेकिंग एवं तलाशी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

गया था। उसने जबरदस्ती छेड़छाड़ करने और पहले भी दुष्कर्म करने की बात बताई। इसके बाद पुलिस ने मामले में धारा 65(1), 74 बीएनएस और धारा 4, 8 पाँसवीं एक्ट जोड़ी। आरोपी मुकेश यादव पिता भारत यादव (19), निवासी धवंईपुर, थाना कटघोरा, जिला कोरबा को 6 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया गया। उसे विशेष न्यायालय (एफटीएससी) कोरबा में पेश किया गया, जहां से न्यायिक

पाँवसो में बरी युवक को हाईकोर्ट ने सजा सुनाई

जगदलपुर। पाँवसो मामले में हाईकोर्ट ने जिला अदालत के फैसले को पलटते हुए जगदलपुर के नेगीगुड़ा निवासी 26 वर्षीय रजत बोस को 20 साल की सजा सुनाई है। जिला अदालत ने पहले आरोपी को मामले में बरी कर दिया था। इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की डबल बेंच में हुई। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश रवींद्र कुमार की पीठ ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आरोपी को आत्मसमर्पण के लिए समय दिया गया था। तय अवधि में सरेंड़ नहीं करने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।

धमतरी में जीएसटी चोरी का बड़ा खुलासा महाराष्ट्र से भरकर लाई गई थी साइकिलें विभाग ने लगाया जुर्माना



श्रीकंचनपथ न्यूज

धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले महाराष्ट्र से बिना बिल के अवैध रूप से साइकिल लाकर बेचने का मामला सामने आया है। स्थानीय व्यापारियों की सतर्कता से जीएसटी चोरी का बड़ा खेल उजागर हुआ। बिना किसी वैध दस्तावेज, परमिशन और बिना जीएसटी नंबर के अवैध रूप से भारी मात्रा में साइकिलें बेची जा रही थी। महाराष्ट्र से आया एक व्यक्ति एक बड़े ट्रक में भरकर भारी मात्रा में साइकिलें बेचने के लिए धमतरी लाया था। उसने स्थानीय स्तर पर न तो प्रशासन से व्यापार करने की कोई अनुमति ली थी और न ही उसके पास कोई वैध जीएसटी नंबर था। वह सीधे तौर पर नियमों को ताक पर रखकर धमतरी के बाजार में साइकिलों की बिक्री कर रहा था। स्थानीय चेंबर ऑफ कॉमर्स धमतरी के स्थानीय पदाधिकारियों और व्यापारियों को लगी, तो वे

तुरंत भारी संख्या में मौके पर पहुंच गए। व्यापारियों ने बिना वैध दस्तावेजों के हो रही इस बिक्री की शिकायत जीएसटी विभाग से की। राज्य कर विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जब दस्तावेजों की जांच की, तो उक्त व्यक्ति के पास व्यापार से संबंधित कोई भी वैध परमिशन या कागजात नहीं मिले।

धमतरी जीएसटी विभाग की कमिश्नर अहिल्या शुक्ला के नेतृत्व में टीम ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। कमिश्नर जीएसटी विभाग धमतरी अहिल्या शुक्ला ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि कोतवाली के पास बिना अनुमति के साइकिलों की बिक्री की जा रही है। हमारी टीम ने जांच की, तो पाया कि इनके पास यहाँ व्यापार करने की कोई वैध परमिशन नहीं थी। नियमों का उल्लंघन करने के कारण इनके खिलाफ कैजुअल टैक्स और नियमानुसार जुर्माने की सख्त कार्रवाई की जा रही है।

टूटकर गिरी एलटी लाइन, करंट से कोटवार की मौत

श्रीकंचनपथ न्यूज

बिलासपुर। बिलासपुर में खेत में टूटकर गिरे एलटी लाइन के करंट प्रवाहित तार की चपेट में आने से कोटवार की मौत हो गई। हादसे के बाद 5 दिन तक उसका शव खेत में ही पड़ा रहा। परिजन उसे लापता समझकर तलाश करते रहे। बिजली लाइन सुधारने पहुंचे कर्मचारियों ने खेत में शव देखा, तब घटना का पता चला।

घटना बिल्हा थाना क्षेत्र की है। ग्राम सेवती निवासी कमलदास (30) कोटवार था। परिजनों ने बिजली विभाग की रखरखाव व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। परिजनों के मुताबिक, 30 सितंबर की सुबह वह फसल



देखने के लिए खेत गया था। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में उसकी तलाश की। कोई सुराग नहीं मिलने पर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। पुलिस तलाश में जुटी रही।

4 अक्टूबर को बिजली कर्मचारी टूटे तार की मरम्मत करने



खेत पहुंचे। इसी दौरान उनकी नजर आँधे मुंह पड़े एक व्यक्ति के शव पर पड़ी। शव काफी हद तक गल चुका था और बिजली के तार से चिपका हुआ था। कर्मचारियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।

बिल्हा पुलिस मौके पर पहुंची। शव की पहचान कमलदास के रूप में हुई है। पंचनामा कार्रवाई के बाद

शव को पोस्टमार्टम के लिए सिम्स भेज दिया। थाना प्रभारी तोप सिंह नवरंग ने बताया कि शव पुराना होने के कारण सड़ चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की वजह स्पष्ट होगी।

ग्रामीणों के मुताबिक, खेत बरतौरी क्षेत्र में आता है। टूटे तार की जानकारी बरतौरी के जेई रोशन श्रीवास को करीब 10 दिन पहले दी गई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद बिजली लाइन की मरम्मत में देरी हुई।

वहीं, जेई रोशन श्रीवास ने इस आरोप से इनकार किया है। उनका कहना है कि 4 अक्टूबर को ग्रामीण कार्यालय पहुंचे और एलटी लाइन टूटने की जानकारी दी। उसी दिन कर्मचारियों को सुधार के लिए खेत भेजा गया था। वहां कमलदास का शव मिला।

जिला अस्पताल के शौचालय में मिला नवजात का शव

गौरेला। जिला अस्पताल के महिला शौचालय में एक अज्ञात नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस घटना ने जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने नवजात के शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को सुरक्षित रखवा दिया है। गौरेला पुलिस फिलहाल नवजात की पहचान और घटना से जुड़े लोगों की तलाश में जुटी है। जरूरत पड़ने पर मामले में डीएनए टेस्ट भी कराया जा सकता है, ताकि नवजात की पहचान और मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा सके। जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलने के साथ ही सीसीटीवी निगरानी प्रणाली की प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) जिला-बालोद (छ.ग.)
//निविदा सूचना //
क्रमांक/आब./निविदा/2026/2952 बालोद, दिनांक 05/10/2026
सर्वसाधारण की विशेष जानकारी के लिए। यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि शासन के निर्देशानुसार मिर्सीटोला, ग्राम पंचायत क्षेत्र में मदिरा विक्रय हेतु नवीन कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान मिर्सीटोला एवं जिले में संचालित करहीभदर, ग्राम पंचायत क्षेत्र में मदिरा विक्रय हेतु विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान करहीभदर के लिए भवन / स्थल किराये पर लिये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदाकार, निविदा शर्तों के अधीन तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के बंद लिफाफे, एक बड़े लिफाफे में रख कर बंद लिफाफा दिनांक 27.10.2026 को दोपहर 02:00 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी सह जिला प्रबंधक सी.एस.एम.सी.एल. जिला-बालोद में जमा कर सकेंगे। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। तकनीकी निविदा उसी दिन सार्यं 04:00 बजे निविदा मूल्यांकन हेतु गठित समिति के समक्ष खोला जावेगा।
निविदा के नियम / शर्तों की जानकारी एवं निविदा प्रपत्र, जिला प्रबंधक सी.एस.एम.सी.एल. जिला-बालोद के पक्ष में देय राशि रु 1180/- (अक्षरी एक हजार एक सौ अस्सी रु.) (जी.एस.टी. सहित) का बैंक ड्राफ्ट (किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी) जमा कर कार्यालयीन कार्यदिवस एवं समय में कार्यालय जिला प्रबंधक सी.एस.एम.सी.एल. जिला-बालोद से प्राप्त किया जा सकता है।
(कलेक्टर महोदया द्वारा अनुमोदित)
जिला आबकारी अधिकारी हेतु कलेक्टर
जिला-बालोद (छ.ग.)
जी-262703775/3

भिलाई मसाला उद्योग

शुद्ध कुटे हुए मसाले,पापड़, अचार, बड़ी, जड़ी-बूटी, जचकी का सामान इत्यादि

128, ए- मार्केट, सेक्टर-6, भिलाई, फोन. 2284508, मो. 9826137766



मातृ शक्ति को नमन मातृत्व का सम्मान



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

मिनीमाता महतारी जतन योजना



पंजीकृत महिला निर्माण
श्रमिकों को पहले दो प्रसव
पर प्रत्येक प्रसव हेतु

₹20,000

की आर्थिक सहायता



सुरक्षित मातृत्व
स्वस्थ भविष्य



माँ और शिशु
का बेहतर स्वास्थ्य



सशक्त महिला
सशक्त परिवार



श्रमिकों के सम्मान
की दिशा में बड़ा कदम



सुशासन से समृद्धि की ओर

ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in